भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 65

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं

***65. श्री अजय भट्टः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तराखंड राज्य सरकार से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने पेयजल योजनाओं में केन्द्रीय हिस्से को कम कर दिया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (ग): उत्तर का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं” के संबंध में श्री अजय भट्ट द्वारा पूछे गए दिनांक 04.12.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *65 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जेजेएम के लिए आवंटित निधि की शेष राशि जारी करने के लिए विभाग को इस प्रकार के दो अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) को मंजूरी दी थी और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग पूरी उपलब्ध निधि का उपयोग कर लिया गया है।

जेजेएम के तहत मिशन अवधि के दौरान जेजेएम के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में यथाउल्लिखित अनुमोदित मानदंडों के अनुसार धनराशि आवंटित की गई थी, जिसका अनुपात विवरण निम्नानुसार है:

- हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों, विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों (उत्तराखंड सहित) के लिए **90:10**,
- विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए **100%**, और
- अन्य राज्यों के लिए **50:50**

इस विभाग में केन्द्रीय हिस्से के अनुपात को कम करने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****